किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय ऐतिहासिक : डॉ मोहन

सीएम ने मीडिया से कहा- अब बड़ी परियोजनाओं को गति मिलेगी और किसान भी होंगे लाभान्वित

भोपाल, 22 अप्रैल. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किसानों को कृषि भूमि के अधिग्रहण पर मुआवजा बाजार दर से चार गुना देने के आज के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे बड़ी परियोजनाओं को गति मिलेगी.

उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसानों के मुआवजे संबंधी मामले संवाद के जरिए सुलझाए जा सकेंगे. डॉ यादव ने बुधवार देर शाम संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि सरकार इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है और यह ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व फैसला है. किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के अधिग्रहण के बदले बाजार दर -गाइडलाइन के अनुसार- से चार गुना मुआवजा मुहैया कराया जाएगा, जो अब तक दोगुना था. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल और जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और किसानों के हित में जुड़े विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर इस पर फैसला लिया गया है. उन्होंने दोहराया कि सरकार किसानों के हित में कार्य करने वाली है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि किसी परियोजना के तहत किसानों की भूमि अधिग्रहण करने के एवज में उन्हें पहले मुआवजा दे दिया गया है, तो भी उनके हितों को ध्यान में रखकर नए फैसले के अनुरूप कदम उठाए जाएंगे.

गेहूं खरीदी पर भी पूरी नजर है सरकार की

डॉ यादव ने कहा कि राज्य सरकार इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का कार्य कर रही है. केंद्र सरकार से यह कोटा बढ़वाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक से किसानों का गेहूं खरीदा जा सके. उन्होंने बताया कि इस बार गेहूं की फसल राज्य में काफी ज्यादा हुई है.

विपक्ष का काम आरोप लगाना, हम अपना कार्य करते हैं

एक सवाल के जवाब में डॉ यादव ने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं का कार्य सिर्फ आरोप लगा देना है. हम अपना कार्य कर रहे हैं. विपक्ष ने तो यह भी कहा था कि लाड़ली बहना योजना बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

प्रदेश में कई हिस्सों में पारा 43 डिग्री पहुंचा

10 जिलों में लू का अलर्ट जारी

भोपाल, 22 अप्रैल. मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रदेश के कई शहरों में तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है, जबकि रातें भी सामान्य से अधिक गर्म बनी हुई हैं.

सबसे अधिक तापमान खजुराहो और नर्मदापुरम में दर्ज किया गया, जहां पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन सहित कई बड़े शहरों में भी तेज गर्मी का असर देखा गया. दिन में सुबह से ही गर्म हवाएं चलने लगीं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ. प्रदेश के 10 जिलों में ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रतलाम, झाबुआ, धार और अलीराजपुर में लू का अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में दोपहर के समय हालात और अधिक गंभीर हो सकते हैं.

ग्वालियर, सीधी, रीवा, सतना, सागर, दमोह और नरसिंहपुर जैसे जिलों में भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल राहत के कोई बड़े संकेत नहीं हैं और गर्मी का असर अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है. रात के समय भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है.

दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें

कई शहरों में न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच दर्ज किया गया, जिसे 'वॉर्म नाइट' की स्थिति माना जाता है. पूर्वी मध्यप्रदेश के कुछ इलाकों में हल्के बादल जरूर छाए, लेकिन इससे तापमान में विशेष गिरावट नहीं आई. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. लोगों से अपील की गई है कि वे दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं, हल्के सूती कपड़े पहनें और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें.

उज्जैन में 30 हजार करोड़ के काम जारी, हाउसिंग बोर्ड के हाथ खाली

- न जमीन, न योजना, न विभाग का विजन
- सिंहस्थ विकास में हाउसिंग बोर्ड गायब
- आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया

प्रमोद व्यास

उज्जैन. सिंहस्थ 2028 को लेकर शहर में जहां करीब 30 हजार करोड़ के विकास कार्य तेज गति से चल रहे हैं, वहीं उज्जैन हाउसिंग बोर्ड पूरी तरह हाशिए पर नजर आ रहा है. हालात ऐसे हैं कि बोर्ड के पास न कोई जमीन बची है, न कोई नई योजना, और न ही सिंहस्थ को लेकर कोई ठोस विजन दिखाई दे रहा है.

करीब 35 से 40 अधिकारी-कर्मचारी होने के बावजूद विभाग में जनहित से जुड़ा कोई बड़ा काम नहीं हो रहा. ऐसे में 'आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया' जैसी स्थिति बन गई है, जहां बिना काम के सरकारी वेतन जारी है और नतीजा शून्य नजर आ रहा है.

70 करोड़ के बंगले, लेकिन फायदा नहीं

राजस्व कॉलोनी में करीब 70 करोड़ की लागत से अधिकारियों-कर्मचारियों के बंगले बनाए जा रहे हैं, इसमें भी बोर्ड को सीधा आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा. ठेकेदार को भुगतान के बदले जमीन दी जा रही है, जिससे हाउसिंग बोर्ड केवल मध्यस्थ बनकर रह गया है और उसे महज 6% का लाभ मिल रहा है.

योजनाओं का सूखा, जिम्मेदारियों का बोझ

हाउसिंग बोर्ड के जिम्मे उज्जैन, देवास और शाजापुर के साथ-साथ उपायुक्त कार्यालय होने के कारण रतलाम, मंदसौर और नीमच तक का दायरा आता है. बावजूद इसके कोई नई आवासीय या व्यावसायिक योजना धरातल पर नहीं उतर रही. पहले जहां बोर्ड आम जनता को कम कीमत पर मकान और दुकान उपलब्ध कराता था, वहीं अब यह व्यवस्था लगभग खत्म होती नजर आ रही है.

अधिकारियों के पास न टीम, न प्लान-वर्तमान में कार्यपालन यंत्री निर्मल गुप्ता से लेकर उपायुक्त प्रबोध पराते समेत अन्य अधिकारियों के पास न पर्याप्त टीम है, न कोई ठोस योजना. हाल ही में पदस्थ हुए उपायुक्त पराते भी रिटायरमेंट के करीब हैं, जिससे दीर्घकालिक योजना बनना और भी मुश्किल नजर आ रहा है.

ऑनलाइन सिस्टम पर भी सवाल-पुरानी योजनाओं के दस्तावेज ऑनलाइन करने की पहल भी सफल नहीं हो पाई. हितग्राहियों के दस्तावेज बार-बार रिजेक्ट होने और भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी की शिकायतें सामने आने से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

दूसरे विभागों के पास काम की भरमार-नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, विकास प्राधिकरण, पुलिस हाउसिंग, स्मार्ट सिटी, सेतु निगम और एमपीआरडीसी जैसे विभागों को सिंहस्थ के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट सौंपे गए हैं, जहां काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसके विपरीत हाउसिंग बोर्ड के हाथ लगभग खाली हैं.

मुलाकातें हुईं, लेकिन नतीजा शून्य-नवभारत को मिली जानकारी के अनुसार हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कलेक्टर, संभाग आयुक्त और सिंहस्थ मेला प्रशासन से मुलाकात कर अपनी स्थिति बता चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट बोर्ड को नहीं सौंपा गया.

चर्चे हुए आम-शहर में चर्चा है कि जिस विभाग का मूल काम आवास और व्यवसायिक योजनाएं बनाना था, वही आज निष्क्रिय हो गया है. ऐसे में जरूरत है कि सिंहस्थ 2028 के कार्यों में हाउसिंग बोर्ड को भी शामिल किया जाए, ताकि एक ओर विभाग सक्रिय हो और दूसरी ओर आम जनता को राहत मिल सके. कुल मिलाकर जब पूरा शहर विकास की रफ्तार पकड़ चुका है, तब हाउसिंग बोर्ड का खाली बैठना न सिर्फ विभाग के सिस्टम पर सवाल खड़े करता है, बल्कि जनहित के अवसर भी खोता नजर आता है.

मैं तो अभी आया हूं...

उज्जैन में पहले पदस्थ रहा हूं. अभी वापस सरकार ने तबादला करके उज्जैन हाउसिंग बोर्ड भेजा है, उपायुक्त के पद पर पदभार ग्रहण कर लिया है. कलेक्टर सर से लेकर कमिश्नर सर से मिले हैं आगे की योजनाएं बनाई जा रही हैं.

- प्रबोध पराते, हाउसिंग बोर्ड, उपायुक्त उज्जैन

सिंहस्थ 2028 की तैयारियां हुईं तेज

समीक्षा बैठक को डीजीपी मकवाणा ने किया संबोधित

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 अप्रैल. सिंहस्थ 2028 की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है. पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने उज्जैन में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस विशाल धार्मिक आयोजन को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यापक रणनीति प्रस्तुत की.

मकवाणा ने सिंहस्थ को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बताते हुए कहा कि आयोजन को उन्नत तकनीक, विभिन्न एजेंसियों के समन्वय और जनभागीदारी के माध्यम से संपन्न किया जाएगा. बैठक की प्रमुख उपलब्धियों में "पुलिस ड्यूटी पोर्टल" का शुभारंभ शामिल रहा, जिसे ई-एचआरएमएस प्रणाली से जोड़ा गया है.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राकेश गुप्ता ने भीड़ प्रबंधन, यातायात दबाव, वीआईपी मूवमेंट और आपातकालीन स्थितियों जैसी संभावित चुनौतियों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनसे निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति तैयार की गई है. करीब 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन के अनुमान को देखते हुए उन्नत निगरानी तंत्र और राज्य व केंद्रीय बलों की समन्वित तैनाती की योजना बनाई जा रही है.

महिलाओं के साथ छल कर रही भाजपा सरकार : यश

जबलपुर, 22 अप्रैल. महिला आरक्षण बिल पर घमासान शुरू हो गया है. मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखे सवाल उठाए हैं. पत्रकारवार्ता के दौरान यश घनघोरिया ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के अधिकारों के साथ छल कर रही है और उन्हें वास्तविक राजनीतिक भागीदारी से वंचित रख रही है. भाजपा की नीतियां महिला विरोधी हैं और महिला आरक्षण बिल केवल दिखावे तक सीमित है. इस दौरान उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि इस बिल के जरिए महिलाओं को वास्तविक अधिकार देने के बजाय इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

सांसद के भाई ने कुएं में कूदकर दी जान, इलाके में सनसनी

नवभारत न्यूज़

खंडवा. खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के बड़े भाई विश्वनाथ उर्फ बाडू पाटिल (58) ने बुधवार तड़के आत्महत्या कर ली. घटना बुरहानपुर जिले के बोहरड़ा गांव की है, जहां उन्होंने अपने ही खेत के कुएं में कूदकर जान दे दी.

सुबह करीब 4 बजे हुई इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और गोताखोरों की मदद से करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. बुरहानपुर एसपी ने इसे प्रथम दृष्टया आत्महत्या बताया है. घटना की खबर मिलते ही दिल्ली में मौजूद सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल तुरंत बुरहानपुर के लिए रवाना हो गए. उनके बोहरड़ा स्थित घर पर समर्थकों और रिश्तेदारों की भीड़ जुट गई है. क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि भी शोक जताने पहुंचे. गुरुवार को पैतृक गांव बोहरड़ा में अंतिम संस्कार किया जाएगा. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. घटना के बाद क्षेत्र में भाजपा के सभी निर्धारित कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं.

महिला आरक्षण को लेकर प्रदर्शन

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 अप्रैल. महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में महिला कांग्रेस ने बुधवार को भोपाल में जोरदार प्रदर्शन किया. सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरीं और सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया.

प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर केवल लॉलीपॉप दे रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब प्रशासन ने मार्च को रोकने का प्रयास किया. पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुसार, उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए और नहीं मानने पर कई महिलाओं को जबरन हिरासत में लिया गया. इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की भी खबर है तथा पुलिस पर बल प्रयोग के आरोप लगाए गए हैं. रीना बोरासी ने कहा कि प्रदेशभर में ऐसे प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं. उन्होंने भाजपा पर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में है तथा इसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए.

लूट का चंद घंटों में खुलासा, 3 गिरफ्तार

धार. जिले के धामनोद क्षेत्र में हुई लूट की घटना का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नगदी और दो मोटरसाइकिल बरामद की हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार धामनोद थाना क्षेत्र में बगवानिया और मुहाड़ रोड के बीच कल रात ग्राम उमरिया निवासी गोपाल बारिया (23) से तीन बदमाशों ने चाकू से हमला कर नगदी और बाइक लूट ली थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने रात्रि गश्त टीम के साथ आसपास करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र में सर्चिंग शुरू की. थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे के नेतृत्व में पुलिस ने लूटी गई बाइक के नंबर के आधार पर तलाश तेज की.

एमपी में किसान की मौत पर सियासी बवाल

उमंग सिंघार ने शोक संवेदना व्यक्त की

सिंघार ने किसान की कथित आत्महत्या को बेहद दुखद बताया

विशेष संवाददाता

भोपाल/विदिशा, 22 अप्रैल. मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विदिशा जिले की शमशाबाद तहसील के सांगुल गांव पहुंचकर दिवंगत किसान कालूराम जाट के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की.

उन्होंने इस घटना के पीछे प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाया. शोकाकुल परिवार से मुलाकात के दौरान सिंघार ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाते हुए एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित रघुवंशी सहित अन्य स्थानीय नेता भी मौजूद रहे. सिंघार ने किसान की कथित आत्महत्या को "बेहद दुखद" बताते हुए कहा कि अपनी ही जमीन और सम्मान के लिए संघर्ष करना व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि शासन और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

नेता प्रतिपक्ष ने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच, दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की. उन्होंने स्थानीय एसडीएम को भी विस्तृत जांच के निर्देश दिए और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया.

आरोप — नीतियों और प्रचार के जरिए किसानों को किया जा रहा गुमराह

फसल खरीद को लेकर कांग्रेस ने जताई चिंता

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 अप्रैल. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुणाल चौधरी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी सरकार पर किसानों के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार जिस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष बता रही है, वह वास्तव में किसान बदहाली वर्ष बन गया है.

इस दौरान मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान और प्रवक्ता राहुल राज भी उपस्थित रहे. चौधरी ने गेहूं खरीदी में देरी और सीमा तय करने को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि लगभग 19.4 लाख किसानों ने करीब 160 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का पंजीयन कराया है, जबकि सरकार ने मात्र 78 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया है. उन्होंने कहा कि खरीदी की रफ्तार इतनी धीमी है कि तय समय सीमा में लक्ष्य पूरा होना मुश्किल दिख रहा है, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं. उन्होंने नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि नीतियों और प्रचार के जरिए किसानों को गुमराह किया जा रहा है. कांग्रेस नेता ने खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाओं, भुगतान में देरी और मक्का व प्याज जैसी फसलों के गिरते दामों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने व्यवस्था को अव्यवस्थित और संदेहास्पद बताते हुए सरकार से तत्काल खरीदी, पूरी उपज की खरीद और किसानों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की.

किसानों के समर्थन में सत्याग्रह

भोपाल. किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस सेवादल 23 अप्रैल से 24 घंटे का सत्याग्रह एवं उपवास आंदोलन आयोजित करेगा. यह कार्यक्रम जवाहर भवन, रोशनपुरा में प्रातः 11:30 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन तक चलेगा. संगठन ने समर्थन मूल्य, फसल खरीदी में अनियमितता, भुगतान में देरी और प्रशासनिक उपेक्षा जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है. इस आंदोलन में सेवादल, महिला सेवादल और यंग ब्रिगेड के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे. प्रदेश मुख्य संगठक अवनीश भार्गव ने सभी से अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है.

बीड़ी जलाते समय झुलसे बुजुर्ग की मौत

ग्वालियर. जिले में बीड़ी जलाते समय गिरी चिंगारी से एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की झुलसकर मौत हो गई. पुलिस सूत्रों के अनुसार माधौगंज थाना क्षेत्र स्थित शीतला माता मंदिर के पास पान पत्ते की गोठ निवासी काशीराम कुशवाह घर के बाहर बने मंदिर पर बैठे थे. इसी दौरान उन्होंने लाइटर से बीड़ी जलाई, तभी चिंगारी उनके कपड़ों पर गिर गई और कुछ ही देर में आग भड़क उठी. बुजुर्ग की चीख सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तथा पानी और कंबल की मदद से आग पर काबू पाया. गंभीर रूप से झुलसे काशीराम को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.

पेज एक का शेष

संजय झा बने रहेंगे जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

जदयू ने 12 नेताओं को महासचिव बनाया है. इनमें मनीष कुमार वर्मा, आफाक अहमद खान, श्याम रजक, अशोक चौधरी, रोशन सिंह कुशवाहा, राम सेवक सिंह, कविता देवी, कपिल हंसदेव पटेल, राज सिंह मान, सुनील कुमार उर्फ इंजीनियर सुनील, हर्षवर्धन सिंह और मौलाना गुलाम रसूल बलियावी शामिल हैं. इसके अलावा राजीव रंजन प्रसाद को प्रवक्ता सह सचिव बनाया गया है. पार्टी के सात सचिव बनाए गए हैं, जिसमें रवींद्र प्रसाद सिंह, विद्या सागर निषाद, दयानंद राय, संजय कुमार, मोहम्मद निसार, रूबी नागवंश और निवेदिता कुमारी (कटिहार) शामिल हैं.

जदयू कार्यकारिणी की सूची इस प्रकार है....

नीतीश कुमार- राष्ट्रीय अध्यक्ष
संजय कुमार झा (सांसद)- कार्यकारी अध्यक्ष
चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी (पूर्व सांसद)- उपाध्यक्ष
डॉ. आलोक कुमार सुमन

महासचिव: मनीष कुमार वर्मा, आफाक अहमद खान, श्याम रजक, अशोक चौधरी, रामेश्वर सिंह कुशवाहा, राम सेवक सिंह, श्रीमती कहकशां परवीन, कपिल हरिशचंद्र पाटिल, राजीव सिंह मान, सुनील कुमार उर्फ इंजीनियर सुनील, हरिवंश सिंह, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी. **सचिव:** रविंद्र प्रसाद सिंह, विद्या सागर निषाद, दयानंद राय, संजय कुमार, मोहम्मद निसार, रंजीत नाग, निवेदिता कुमारी, प्रवक्ता, राजीव रंजन प्रसाद संतोष श्रवण

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60